

## झारखंड कैमरून में फॉसे श्रमिकों की सहायता करेगा

### चर्चा में क्यों?

झारखंड के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फॉसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों के समूह को उनके वेतन का आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया है।

### मुख्य बंदि

#### ■ लंबति वेतन और कानूनी गैर-अनुपालन:

- कैमरून में मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड द्वारा नयिोजति श्रमिकों ने तीन महीने से वेतन का भुगतान न कयि जाने का आरोप लगाया।
- झारखंड के मुख्यमंत्री ने श्रम आयुक्त को नयिोक्ताओं और बचौलियों के वरिद्ध **प्रथम सूचना रपिरट (FIR)** दर्ज करने का नरिदेश दया।
- FIR में **अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधनियिम, 1979 के उल्लंघन** का उल्लेख कया गया है, जसिमें पंजीकरण या अपेक्षति लाइसेंस के बनिा श्रमिकों को वदिश भेजना भी शामिल है।
- झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गरिडीह ज़िलों में FIR दर्ज की गई।

#### ■ वेतन भुगतान अद्यतन:

- ट्रांसरेल लाइटिंग ने कहा क श्रमिकों को प्रता माह 100 अमेरिकी डॉलर का भुगतान कया गया था तथा शेष राश उनके भारतीय खतों में स्थानांतरति करने का वादा कया गया था।
- श्रम वभाग ने कंपनी से अनुबंध, वेतन रकिॉर्ड और अन्य प्रासंगकि दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध कया है।
- आवश्यक कार्रवाई के लयि **प्रवासी संरक्षक (POE)** और अन्य प्राधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

#### ■ कूटनीतिक प्रयास:

- भारतीय उच्चायोग और **वदिश मंत्रालय** कंपनी और फॉसे हुए श्रमिकों के बीच बातचीत को सकरयि रूप से सुवधाजनक बना रहे हैं।
- नयितरण कक्ष की टीमें श्रमिकों और अधकारियों की सुरक्षा सुनिश्चति करने के लयि उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं।
- अधकारियों ने चेतावनी दी क पूरण वेतन का भुगतान न करने पर **ठेकेदारों के साथ समझौते रद्द कयि जा सकते हैं।**

#### ■ हस्तक्षेप के पछिले मामले:

- जुलाई 2024 में, मुख्यमंत्री ने कैमरून से 27 फॉसे श्रमिकों को वापस लाने के लयि हस्तक्षेप कया।
- मलेशया में फॉसे 50 श्रमिकों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं, जो वशिखापत्तनम पहुँच चुके हैं और उनके शीघ्र ही घर लौटने की आशा है।

## अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधनियिम, 1979

- इस अधनियिम का उद्देश्य अंतर-राज्यीय प्रवासियों के रोज़गार और उनकी सेवा की शर्तों को वनियिमति करना है।
- यह प्रत्येक ऐसे प्रतषिठान पर लागू होता है जो **अन्य राज्यों से आए पाँच या अधिक प्रवासी कर्मकारों को नयिोजति करता है** अथवा यद उसने पछिले 12 महीनों में कसि भी दनि **पाँच या अधिक ऐसे कर्मकारों को नयिोजति कया हो।**
- यह उन ठेकेदारों पर भी लागू होता है जनिहोंने समान संख्या में अंतर-राज्यीय श्रमिकों को रोज़गार दया हो।
- इसमें ऐसे प्रतषिठानों के पंजीकरण की व्यवस्था की परकिल्पना की गई है। मुख्य नयिोक्ता को संबंधति प्राधिकारी से **पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बनिा अंतरराज्यीय श्रमिकों को नयिोक्त करने से प्रतबंधति कया गया है।**
- कानून में यह भी प्रावधान है क **प्रत्येक ठेकेदार जो एक राज्य से दूसरे राज्य में तैनाती के लयि श्रमिकों की भरती करता है, उसे ऐसा करने के लयि लाइसेंस प्राप्त करना होगा।**

